भारत में प्रगति और विकास की बाधाएं भारत बार्सियर्स MandhataGlobal.com

साइट का उद्देश्य सिस्टमिक असफल बिंदुओं को हाइलाइट करना है जो कि प्रगति और विकास के लिए रोडब्लॉक हैं, उम्मीद है कि देश और सरकार इन मुद्दों को बढ़ाने के लिए समाधान पर काम करेगी।

सामग्री की तालिका

	1
1। जनसंख्या	2
2. मौलिकता और अभिनवकी कमी	3
रक्षा और आयुध पर3. Overspending- हथियारमें फंस गए खरीदने जाल	7
4. शौचालय	8
5. सीवेज	10
6. प्रदूषण जलमार्ग में	11
7. मानसून की वर्षा - जल निकासी की समस्या है, भंडारण पानी की कमी झीलों और बांधों में	12
8. विश्वविद्यालयों और पंचायतों सहित रिश्वत और भ्रष्टाचार	13
9। कचरा और सफाई	14
10. प्लास्टिक प्रदूषण	17
11. बहुत से सार्वजनिक छुट्टियों की वजह से राष्ट्रीय उत्पादकता कम है	18
12. भारतीय शिक्षा में संकट	20
13. ग्रामीण विकास	22

1. ओवरपोप्यूलेशन

ओवरपॉप्यूलेशन हमारे अपने अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है। पूरी दुनिया को इस मुद्दे को हल करने की जरूरत है, न केवल कुछ देशों को। मुख्य रूप से चिकित्सा प्रगति और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश अपनी आबादी में पर्याप्त वृद्धि को नजरअंदाज कर अपनी विपत्तियों को और अधिक जोड़ते हैं।

भारत अब 1.2 बिलियन का घर है। इसके अलावा यदि पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, तो इस शताब्दी के मध्य में स्थिर होने से पहले भारत की जनसंख्या 1.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आज जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत अपनी सीमा तक फैला हुआ है। 57 अरबपति भारत की संपत्ति का 70 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं। यह आर्थिक असमानता गरीबी, मुफ्त चिकित्सा सहायता की कमी, सामाजिक सुरक्षा की कमी और बुरी जिंदगी की स्थिति का कारण बनती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन में प्रगति के कारण मुद्दे और भी महत्वपूर्ण हैं। ऑटोमेशन ने आईटी और उत्पादन क्षेत्रों में पहले से होने वाले लाखों नौकरी के नुकसान के साथ 69 प्रतिशत नौकरी के नुकसान की धमकी दी है। ई-कॉमर्स नौकरी में कटौती और कीमतों के कारण अब तक चुनने में असफल रहा है जो स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

अत्यधिक आबादी कामकाजी संस्थानों को अक्षमता की ओर ले जाती है और देश की बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सहायता सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पहलों को अप्रभावी बनाने में सभी योजनाएं बनाती है। इसमें भारत सरकार शामिल है जिसने आजादी के बाद पिछले 69 वर्षों में सुधारों को लागू करने के लिए संघर्ष किया है।

जनसंख्या वृद्धि के परिणाम एक समस्या है कि पूरी दुनिया जल्द ही या बाद में सामना करेगी। पेयजल, सीवेज उपचार, अपर्याप्त वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी, वनों की कटाई और पर्यावरण प्रणालियों के नुकसान के कारण कई पौधों और पशु प्रजातियों का विलुप्त होने, जीवन में खतरनाक हवा और जल प्रदूषण, उच्च शिशु और बाल मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और चरम गरीबी के कारण भूख अधिक आबादी के परिणाम हैं।

अधिकतर लोग अतिसंवेदनशीलता के कारण पहले से ही सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन केवल कुछ ही स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से अवगत हैं। अधिकांश भारतीय शहर बुरी तरह प्रदूषित होते हैं और थोड़ी ताजा हवा होती है। यह अनगिनत वायु रोग और त्वचा संक्रमण की ओर जाता है।

यह सिर्फ भारत का संघर्ष नहीं है, ब्राजील और चीन भी अधिक जनसंख्या के विनाश के साथ सामना कर रहे हैं। अब इस समस्या को हल करने के लिए सभी वैश्विक मंचों को प्रभावी समाधान प्रदान करने का समय है। अतिसंवेदनशीलता केवल जन्म नियंत्रण और जन्म नियंत्रण उपकरणों

तक पहुंच जैसे उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने और हल करने के द्वारा हल की जा सकती है। आइए दुनिया को एक बेहतर कल के लिए तैयार करने में मदद करें।

2. मौलिकता और नवाचार कीमौलिकता और नवाचार की

कमीकमी: इस प्रकार भारत की 'जुगाद' की शाश्वत आदत देश को उखाड़ फेंक रही है।

भारतीय नए लोगों को नवाचार करने के बजाय मेकफिफ्ट विकल्पों की व्यवस्था करने में सक्षम हैं। और यह एक प्रमुख कारण है कि हम अपने 'जुगाद' के लिए प्रसिद्ध क्यों हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों में मौलिकता की कमी है और उन तकनीकों पर भरोसा है जो उम्र के लिए वहां झूठ बोल रहे हैं।

न केवल यह, जब पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की बात आती है तो भारत सूची में आखिरी है। जब नए विचारों और शोधों में निवेश की बात आती है, तो भारत ने 2005 से 2014 तक आर एंड डी पर केवल 0.82% खर्च किया।

जब शिक्षा की बात आती है, तो हमारे पास दिमाग का सबसे चमकीला हो सकता है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों और स्कूलों में बुनियादी ढांचे और नवाचार की कमी है। जबकि दुनिया भर के स्कूल ई-कक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय शैक्षणिक प्रणाली अभी भी बहुमत को पढ़ाने के पारंपरिक तरीके का पालन करती है।

निश्चित रूप से, अस्थायी व्यवस्था हमें थोड़े समय के लिए मदद कर सकती है, लेकिन जब एक सुरक्षित और 'विकसित' भविष्य की बात आती है, तो भारत को बदलाव की सख्त जरूरत होती है।

विश्व बैंक के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, भारतीय कंपनियों के एक बड़े अनुपात में नवाचार में निवेश करने के लिए नीति या मानव संसाधन क्षमताएं नहीं हैं, हालांकि देश के अपने सहकर्मियों की तुलना में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्च के मामले में अनुकूल रूप से किराया है।

इक्विटी, विकास, वित्त और मुख्य अर्थशास्त्री विलियम मालनी ने कहा, "यदि आप प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर अन्य देशों की तुलना में जीडीपी के हिस्से के रूप में आर एंड डी में निवेश करते हैं, तो वास्तव में यह बुरा नहीं करता है" विश्व बैंक में संस्थान।

भारतीय आईटी उद्योगपति और इंफोसिस के सह-संस्थापक, नारायण मूर्ति ने हाल ही में उल्लेख किया है कि भारत ने पिछले 60 वर्षों में दुनिया को 'पृथ्वी हिलाने' का विचार नहीं किया है। यह एक गंभीर अवलोकन है विशेष रूप से आईटी उद्योग और एक प्रतिष्ठित उद्यमी के एक दल से आ रहा है। लेकिन नारायण गलत नहीं है। डेटा दृढ़ता से अपने निष्कर्षों की पुष्टि करता है। भारत सभी नवाचार सूचकांक में खराब किराया।

नवाचार चलाने के लिए भारत में दुनिया के सबसे विरोधी वातावरण में से एक है।

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 56 देशों की हालिया रैंकिंग में 54 वें स्थान पर रही, इस आधार पर कि उनकी घरेलू नीतियां वैश्विक नवाचार का समर्थन करती हैं। टेक्नोलॉजी पॉलिसी थिंक टैंक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ) द्वारा रिपोर्ट (पीडीएफ) में ऐसे देश शामिल हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 9 0% हिस्सा बनाते हैं। आईटीआईएफ ने पहली बार ऐसी रिपोर्ट संकलित की है।

"थाईलैंड, चीन, भारत, अर्जेंटीना, और रूस क्षेत्र नीतियां जो वैश्विक नवाचार प्रणाली से सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए कमजोर वातावरण प्रदान करते समय ये देश व्यापार बाधाओं और अन्य विकृतियों का सबसे व्यापक उपयोग करते हैं।

इसने 14 कारकों की जांच की जो घरेलू नवाचार का पक्ष लेते हैं और वैश्विक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे सहायक कर प्रणाली और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और मानव पूंजी में निवेश। इसने 13 अन्य कारकों का भी आकलन किया- जैसे कि मजबूर स्थानीयकरण और कमजोर बौद्धिक संपदा सुरक्षा - जिसका वैश्विक नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

1. कर
भारत अपने उदार आर एंड डी से संबंधित कर प्रोत्साहनों के आधार पर रैंक किए गए देशों की सूची के शीर्ष पर है। हालांकि, इसमें नवाचार की कमी है क्योंकि यह सहयोगी अनुसंधान एवं विकास कर क्रेडिट (विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, और अनुसंधान संघों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए किए गए व्यय पर प्रस्तावित व्यय), और शोध के बजाय नवाचार को व्यावसायीकरण के लिए प्रोत्साहित करने जैसे अन्य क्षेत्रों में है।

2. मानव पूंजी
एक प्रमुख कारण है कि भारत नवाचार में क्यों लगी है क्योंकि देश प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अन्य देशों की तुलना में कम से कम खर्च करता है। भारत सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर प्रति छात्र केवल 1,248 रुपये (84, 9 78) खर्च करती है, यहां तक कि वियतनाम, इंडोनेशिया या पेरू से भी कम है।

हालांकि, शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों वाले देशों की बात आती है जब भारत मध्य में कहीं है। 25 में, भारत अर्जेंटीना, ब्राजील, पोलैंड और केन्या जैसे देशों से आगे है, शीर्ष 800 विश्व रैंकिंग विश्वविद्यालयों में से 17 के साथ, रिपोर्टों ने संस्थानों का नाम दिए बिना कहा।

फिर भी, देश में शोधकर्ताओं की संख्या 15,000 प्रति 100,000 लोगों की है, जो इस श्रेणी में भारत को पांचवें स्थान पर रखती है। भारत रैंकिंग के नीचे छः देशों में से एक है जब कुल उद्धरणों की बात आती है- एक अकादमिक दस्तावेज जिसे बाद में शैक्षिक अनुसंधान-प्रति 1000 नागरिकों द्वारा संदर्भित किया जाता है।

ऐसा क्यों है कि भारत, यहां तक कि अपने विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ, कांच की छत तोड़ने में सक्षम नहीं है? और अधिक विशेष रूप से, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं हमारे देश में नवाचार में बाधा डालती हैं?

यहां नीचे पांच प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक तुलनाएं हैं जो हमें वास्तविक उत्तर दे सकती हैं:

ए **वेतन प्रतिस्थापन व्यवसाय बनाम उद्यमशीलता**

हमारी आजादी के बाद आर्थिक नीति में समाजवादी पूर्वाग्रह ने निजी उद्यमों के प्रति संदेह की भावना सुनिश्चित की। इसमें बड़ी निर्वाह खेती की जनसंख्या, कम औपचारिक शिक्षा स्तर और सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या की चुनौती शामिल है। और इसलिए यह विकसित हुआ कि कमोडिटी ट्रेडिंग, मरम्मत की दुकानें, और खुदरा बिक्री किसी भी व्यक्ति के लिए भूख से भूख लगी है - कम निवेश, तेजी से नकद प्रवाह, कोई नवाचार जोखिम नहीं है और बहुत कम सरकारी निर्भरता है। ये वास्तविक अर्थ में केवल 'वेतन-प्रतिस्थापन व्यवसाय' थे, जिसका उद्देश्य प्रमोटर की जीवनशैली को बनाए रखने के लिए नकदी प्रवाह बनाना था। व्यापार से मुनाफे में पहला मिलियन घर या कार खरीदने में चला गया। बाद के लाखों दूसरे घर और कार में चले गए, और बहुत आगे।

हालांकि, अभिनव उद्यमों को व्यवसाय में कमाई के पुनर्निवेश की आवश्यकता होती है। भारत की बोझिल सरकारी नीतियों और नौकरशाही चुनौतियों ने सुनिश्चित किया कि विनिर्माण में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को विचारों और उद्यमी भावना के बजाय 'चाई पाणि' (रिश्वत) की जेबदार की जरूरत है। ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया। वे व्यवसाय की नींव के तहत वेतन-जैसे नकदी प्रवाह होने से खुश थे। असली उद्यमिता गायब हो गई। आज, हम व्यापार मूल्य श्रृंखला, बीपीओ और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निचले सिरे पर बने रहे हैं।

बी। **प्रीमियम भुगतानकर्ता बनाम सौदा शिकारी**

भारतीय उपभोक्ताओं के 'कम से कम' रवैये की उत्पत्ति 'वास्तविक मूल्य' का मूल्यांकन करने की हमारी अत्यधिक मनाई गई क्षमता की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कम है। सौदा शिकार पूंजीवाद के वरदान का उदाहरण देने या मांग-आपूर्ति अवधारणाओं को चित्रित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है लेकिन यह गहराई से नवाचार के लिए एक झुकाव है। इनोवेशन लंबी

अवधि के निवेश की मांग करता है और टिकाऊ होने की मांग करता है, यह प्रीमियम को प्रोत्साहित करने और भुगतान करने की बाजार की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि बाजार उस उन्नत इंटेल चिप या आईफोन के लिए भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, तो मूर का कानून कभी भी सच नहीं हो सकता है।

भारत के बाजारों में 'कम से कम' के लिए पूर्वाग्रह है और इसलिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए एक छोटे से व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन भी बाधित हो जाता है। यहां तक कि उद्यमशीलता पिरामिड के शीर्ष पर, यानी बड़े निगमों, नवाचार की कमजोर संस्कृति ने सुनिश्चित किया कि एमएसएमई के लिए कोई आदर्श मॉडल नहीं था। इन बड़ी कंपनियों को एक समान बाजार का सामना करना पड़ा - सौदेबाजी शिकारी - और परिणामस्वरूप सहयोगी उत्पाद विकास के बजाय छोटे मार्जिन वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं को निचोड़ा। उन्होंने बेहतर दक्षता के उत्साह का उपयोग करके नवाचार पर कम लागत को प्रोत्साहित किया। आज भी अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों में यह सच है, खासकर भारतीय ऑटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखला।

सी। **सुरक्षित खिलाड़ियों के विरुद्ध सुरक्षित खिलाड़ी**

सामाजिक सुरक्षा, खराब बीमा प्रवेश, और मौलिक कृषि प्रथाओं की अनुपस्थिति जो मानसून पर निर्भर करती है, ने सुनिश्चित किया है कि परिवार के लिए लड़ाई अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में है और सृजन नहीं है। अभिनव रचनात्मकता की मांग करता है। रचनात्मकता के मार्ग के बाद जोखिम भरा है। मूलभूत बातों के लिए यह लड़ाई अनुमानित पथों और एक सामूहिक संस्कृति के लिए प्राथमिकता की ओर ले जाती है जो ज्ञात से विचलन को हतोत्साहित करती है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने मोल्ड तोड़ने की कोशिश की (और असफल) को "अच्छी कोशिश" के पीछे एक पेट नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें "मैंने आपको बताया था" के कई संस्करण मिल गए हैं। इस प्रकार हमने एक 'सुरक्षित खेल' समाज बनाया है - नियमित शिक्षा पथ, नियमित नौकरियां और नियमित व्यवसाय। जोखिम लेने वाला एक वर्जित रहा है! यह अभी भी व्यवसाय और व्यक्तियों दोनों के लिए है। यह स्कूलों से शुरू होता है और उसके बाद जारी रहता है।

डी। **धन उधारदाताओं बनाम वित्तीय enablers**

औपचारिक वित्त पोषण क्षेत्र में एसएमई उधार मॉडल पुराने, लाभ और सबसे महत्वपूर्ण, संपार्श्विक सुरक्षा के लिए उच्च भार देते हैं। मजबूत विचारधारा और नवाचार करने की क्षमता को देखते हुए बहुत कम महत्व है। इस मानसिकता के साथ, बैंकों के लिए सद्भावना और बौद्धिक संपदा (आईपी) जैसे बैलेंस शीट इंटैंगबिल की सराहना या मूल्यांकन करना मुश्किल है। फाइनेंसरों ने विविधीकरण पर फंसाया है और 'नियमित रूप से पालन' को प्रोत्साहित किया है। ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए संपार्श्विक के बिना किसी भी छोटे उद्यम को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल है। समानांतर वित्त प्रणाली धन उधारदाताओं तक ही सीमित थी, जहां आप "मुझे पैसे दिखाएं" कहने से पहले भी आप जिस ब्याज का भुगतान करते थे, वह प्रिंसिपल से

भी बड़ा हो गया। परी निवेशकों और वीसी के आगमन के साथ, पूंजी तक पहुंच पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है, खासकर नई आयु तकनीक और आईटी-सक्षम स्टार्टअप के लिए। छोटे विनिर्माण व्यवसायों के लिए, आज भी स्थिति अलग नहीं है।

ई। **लोकतंत्र बनाम लोकतंत्र**

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर अपनी हाल की टिप्पणी में सांसद शशि थरूर ने भारत पर अपने पिता को सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा पाखंड बताया। यह कास्टिक है लेकिन खराब नवाचार पर हमारे मामले के लिए एक कड़वा सत्य और उपयुक्त संदर्भ है। एक बिंदु पर, हमने स्वदेशी (स्वदेशी) को प्रोत्साहित करने के बहस के तहत विदेशी (विदेशी) कंपनियों के बाहर निकलने के लिए सुनिश्चित किया लेकिन आयातित गैजेट और आयातित सौंदर्य प्रसाधनों को जारी रखा। हमें पूंजी और प्रौद्योगिकी की जरुरत थी लेकिन एफडीआई की आलोचना की।

वाटरकोलर चर्चाओं ने प्रायः सिंगापुर को स्वच्छता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया लेकिन सुविधा के अनुसार हमने कचरा, सड़क के किनारे या सड़क के बीच फेंकना जारी रखा। भारतीय व्यापारियों ने ईमानदारी के बारे में बात की लेकिन सिस्टम को तेल लगाने के लिए ठीक रहे, जब तक उनके घटिया उत्पादों को सरकारी आदेशों में स्वीकार कर लिया गया। बाहर से बेहतर तकनीक से संरक्षणवाद जन्मजात की तरह लग रहा था। वे भ्रष्टाचार के बोझ के खिलाफ थे लेकिन कर से बचने के लिए वित्तीय वक्तव्यों के 'डॉक्टरिंग' को विवेक पर कोई बोझ नहीं लग रहा था! फिर वहां विलुप्त डिफॉल्टर्स थे जो 'वैध' व्यवसायों की नींव के तहत अक्षम कानूनों और न्यायिक प्रक्रियाओं का लाभ उठाते थे।

जबकि सिस्टम जिस तरह से था, एमएसएमई के पास भी दोष में हिस्सा है। ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से काम करने का एकमात्र समय एक लेवी या आयात का विरोध करना था, और शायद ही कभी भ्रष्ट अधिकारी की अनुचित मांगों के खिलाफ था। वहां कोई भी आत्म-विनियमन नहीं है जो कि सशक्त औद्योगिक संघों का कार्य करता है। लोकतंत्र की सुंदरता जिम्मेदार सामूहिकता में है। कल्पना करें कि क्या औद्योगिक क्षेत्र में सभी एमएसएमई भ्रष्ट बिक्री कर निर्धारक या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी की ब्लैकमेलिंग की मांगों में गुजरने का फैसला नहीं करते हैं! पाखंड की सुंदरता अर्ध-सत्य और सुविधा में है। यह एक सुविधाजनक व्यवस्था रही है जिसने स्थिति को प्रोत्साहित किया और विस्तार से, नवप्रवर्तन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

3. रक्षा और आर्मेंट्स पर आगे बढ़ना - हथियार खरीदने के लिए अमेरिका, यूरोप, रूस जाल में पकड़ा गया

फरवरी 2018 में, भारत ने चुपचाप एक मील का पत्थर पारित किया। अपने वार्षिक बजट की रिहाई से पता चला है कि $ 62 बिलियन पर रक्षा खर्च, अपने पूर्व औपनिवेशिक मास्टर, ब्रिटेन के पीछे चला गया है। केवल अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस अपने सैनिकों पर अधिक भरोसा करते हैं। लगभग एक दशक तक भारत हथियारों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक भी रहा है। सक्रिय जनशक्ति और जहाजों और विमानों की संख्या के मामले में, इसकी सशस्त्र सेनाएं पहले से ही दुनिया के शीर्ष पांच में से हैं।

कुछ कमजोरी भारत की ताकतों के आकार के कारण नहीं हो सकती है, बल्कि उनके आकार के लिए हो सकती है। कई विशेषज्ञ रिपोर्टों के बावजूद, आंतरिक सैन्य सिफारिशों और समिति निष्कर्षों ने भारत के केंद्रीय और क्षेत्रीय आदेशों को एकीकृत करने के लिए बुलाया, इसकी सेना, नौसेना और वायु सेना ने कठोर स्वतंत्र संरचनाओं को बनाए रखा है। जबकि चीन ने हाल ही में अपनी परिचालन बलों को पांच व्यापक क्षेत्रीय आदेशों में सुव्यवस्थित किया है, भारत 17 अलग-अलग एकल-सेवा स्थानीय आदेश बनाए रखता है।

इस बीच रक्षा मंत्रालय, जो कि खरीद और प्रचार के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शॉट्स कहता है, को करियर नौकरशाहों और राजनीतिक नियुक्तियों के साथ काम किया जाता है, जिनमें न केवल तकनीकी ज्ञान की कमी होती है बल्कि पूर्व सैनिकों को भी गुमराह करती है, जो समान रूप से लोगों के लिए बहुत सहानुभूति रखते हैं।

जबकि भारत हथियार और सेना पर अरबों डॉलर खर्च करता है, धन को शौचालय, सीवेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, शिक्षा, जल परियोजनाओं, सड़कों, अधिक आबादी आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं से लिया जाता है।

सबसे दुखद मुद्दा यह है कि हर हथियार निर्माण दुनिया का देश भारत को हथियारों की आपूर्ति करना चाहेगा, न कि क्योंकि वे भारत को पसंद करते हैं, यह पूरी तरह से लाभ उद्देश्यों के लिए है, वे सभी "व्यापार के लिए अच्छा है" के अभ्यास का पालन करते हैं, विशेष रूप से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश।

4. शौचालय

इस गर्मी में भारत में सबसे लोकप्रिय फिल्म शौचालय के बारे में है। यह लगभग तलाक का कारण बनता है। यह एक पिता को अपने वयस्क बेटे को थप्पड़ मारता है। यह आधा में एक गांव विभाजित करता है। लेकिन, आखिरकार, यह एक रोमांस के बारे में है।

कमोड के लिए सिर्फ एक ओडी से अधिक, फिल्म, "शौचालय, एक लव स्टोरी", भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक से बात करती है। इन दिनों भारत में शौचालय एक बड़ा मुद्दा:हैंपर्याप्त नहीं हैंदेश के 1.3 अरब लोगों के लिए, और राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा शौचालय निर्माण अभियान शुरू कर रही है।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात से परेशान हैं कि कितने भारतीय अभी भी खुले में खुद को राहत देते हैं, ने 100 मिलियन नए शौचालयों का निर्माण करने की कसम खाई है।

पूरे देश में, नई शौचालय बढ़ रही हैं, कभी-कभी इतनी तेज़ी से वे किसी भी चीज़ से जुड़े नहीं होते हैं, कहीं भी शौचालय नहीं बनाते हैं जो इतनी फ्लाई-सवार और बदबूदार हैं कि लगभग कोई भी उनका उपयोग नहीं करेगा।
यहां तक कि एक नया मोबाइल फोन ऐप भी है जो लोगों को निकटतम शौचालय कैसे ढूंढता है। "जब प्रकृति कॉल करती है," बिलबोर्ड पढ़ते हैं, "अपने फोन का उपयोग करें!" यह हास्यास्पद है, लोगों के पास सेल फोन हैं लेकिन शौचालय तक पहुंच नहीं है।

सुविधाओं की कमी सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि फिल्म स्पष्ट करती है, लेकिन सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों और मानव गरिमा के मुद्दों पर भी छूती है।

यूनिसेफ के मुताबिक, लगभग 564 मिलियन भारतीय, लगभग आधी आबादी, अभी भी खेतों, जंगलों, तालाबों के बगल में, राजमार्ग मध्यस्थों और समुद्र तट पर खुली है।

कभी-कभी ग्रामीण महिलाओं को टाउन और यहां तक कि यौन हमले का सामना करना पड़ता है जब वे खुद को राहत देते हैं, इसलिए वे सुरक्षा के लिए अक्सर सुबह से पहले छोटे समूहों में यात्रा करते हैं। महिलाओं के अधिकार वकील जगमती सांगवान ने कहा, "यह एक असली समस्या है।" "इतनी सारी महिलाएं, विशेष रूप से भूमिहीन महिलाएं, जब वे बाथरूम में जाते हैं तो बहुत हिंसा का सामना करते हैं।"

क्या कोई वास्तव में हैरान है कि भारत के लगभग 1.2 अरब लोगों के घर में शौचालय नहीं है? ज़रुरी नहीं। भारत मानव विकास रिपोर्ट थोड़ी देर के लिए यह कह रही है। गांवों में स्थिति बदतर है, जहां दो तिहाई घरों में शौचालय नहीं हैं। खुले शौचालय में वृद्धि हुई है, और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है जिसमें बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच के बिना लोगों के आधे अनुपात में कमी शामिल है।

खुले शौचालय के लिए शौचालयों और प्राथमिकता की कमी समाज में एक सांस्कृतिक मुद्दा है जहां आदत वास्तव में सामाजिक उत्पीड़न को कायम रखती है, जैसा कम जाति मानव स्वेवेंजर्स और सफाई करने वालों के कम लेकिन निरंतर अस्तित्व से साबित हुआ है?

भारत की स्थायी शर्मनाक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से निहित है। आजादी के बाद आधा शताब्दी से अधिक, कई भारतीय खुद को खुले और कूड़े में खुद को राहत देते रहते हैं, लेकिन अपने घरों को निर्दोष रूप से साफ रखते हैं। हां, राज्य स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करने में असफल रहा है, लेकिन लोगों को भी दोष लेना चाहिए।

गुड़गांव के अपस्टार्ट उपनगर में, शिक्षित, ऊपर की ओर मोबाइल, समृद्ध पड़ोसियों ने अपने पालतू कुत्तों को अपने नौकरों के साथ बाहर भेज दिया और गड़बड़ी को साफ करने से इंकार कर दिया। जब तक उनका कॉन्डोमिनियम साफ हो, तब तक यह ठीक है। ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि सरकार सभी बुराइयों की जड़ पर है।

शौचालयों की कमी पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जब पर्यटक देश के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो उन्हें कोई भी उपलब्ध शौचालय नहीं मिल सकता है या शौचालय खराब स्थिति में खराब अनुभव और नकारात्मक प्रचार छोड़ रहे हैं।

हमें यह सीखने के लिए कि यह कैसे किया जाता है, हमें अन्य देशों में टॉयलेट सिस्टम, शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता और शौचालयों की सफाई का अध्ययन करना चाहिए। देश की प्रगति में बाधा डाली जाएगी, हम शौचालय और सीवेज मुद्दे को अनदेखा करते हैं।

एक और बड़ी अदृश्य समस्या पर्यटकों के लिए शौचालय की सुविधा है, किसी भी शहर, शहर या पर्यटक आकर्षण लेते हैं और यह शौचालय खोजने के लिए एक दुःस्वप्न है और एक स्वच्छ स्वच्छता सुविधा है, इसलिए अधिकांश पर्यटकों को मूत्राशय नियंत्रण में भाग लेना पड़ता है जब तक वे वापस नहीं आते होटल।

5. सीवेज

इंडिया देश में सीवेज निपटान पर डाउन टू अर्थ पत्रिका की नवीनतम कवर स्टोरी "शहरी शिट" के मुताबिक, दिन में 1.7 मिलियन टन फिकल कचरा पैदा करता है। दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी केंद्र विज्ञान और पर्यावरण (सीएसई) द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि जब सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन की बात आती है तो भारत इस बिंदु को कैसे खो रहा है, ज्यादातर शहरों में कोई कचरा नहीं है कि कचरे को कैसे व्यक्त किया जाए या इसका ईलाज करो। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि उत्पन्न सीवेज का 78 प्रतिशत इलाज नहीं किया जाता है और नदियों, भूजल या झीलों में इसका निपटारा किया जाता है।

समाचार पत्रों जैसे कि "घरों के आधे हिस्से में फोन हैं लेकिन शौचालय नहीं हैं," और भारत सरकार और गैर-लाभकारी संस्थाओं के 48 प्रतिशत भारतीयों को शौचालय मुहैया कराने के मेहनती प्रयासों का सुझाव है कि पर्याप्त शौचालय भारत की स्वच्छता को हल करेंगे संकट। हकीकत में, जबकि शौचालय समाधान का एक आवश्यक हिस्सा हैं, एक तर्कसंगत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा मुद्दा यह है कि भारत के सीवेज को कैसे शामिल किया जाए और उसका इलाज कैसे किया जाए। वर्तमान में, सीवेज का 93 प्रतिशत उपचार के बिना तालाबों, झीलों और नदियों के लिए अपना रास्ता पाता है।

1)। इलाज न किए गए सीवेज भारत में जल स्रोतों का अग्रणी प्रदूषक है, जिससे दस्त सहित कई बीमारियां पैदा होती हैं (जो सालाना 350,000 भारतीय बच्चों को मार देती है
)। कृषि संदूषण, और पर्यावरण गिरावट। शहरी गरीब अक्सर गंदे नालियों और नहरों के साथ रहते हैं जिसमें मच्छरों और रोगाणुओं की नस्ल होती है।

भारत के सबसे बड़े शहरों में केंद्रीकृत सीवेज सिस्टम हैं, जो भूमिगत पाइप, पंपिंग स्टेशन और उपचार संयंत्रों से परिपूर्ण हैं। हालांकि, इन प्रणालियों को बनाने और संचालित करने के लिए महंगा है, निर्बाध शक्ति, कुशल ऑपरेटरों और व्यापक रखरखाव की आवश्यकता है। नतीजतन, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उनमें से आधे से भी कम प्रभावी ढंग से काम करते हैं। 3)। और भी, भारत के छोटे कस्ब ऐसे सिस्टम बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कार्यशाला के विशेषज्ञों ने कहा कि मानव उत्सर्जन को ले जाने में दुनिया भर में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जा रहा था। यह पानी का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है, वर्तमान तकनीक - उत्सर्जन को दूर करने और इसे दूर करने के लिए पानी का उपयोग करना-टिकाऊ नहीं था। समाधान, आधुनिक सेप्टिक टैंक और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए साइट पर फिकल कीचड़ प्रबंधन था ताकि एक्सिट्रटा जल निकायों को दूषित न करे। वर्तमान पाइप सीवरेज स्टम सीवेज का इलाज नहीं करते हैं बल्कि इसे दूर ले जाते हैं। वे नदियों और झीलों के लिए जहरीले और अत्यधिक प्रदूषण कर रहे हैं जहां उन्हें डंप किया जाता है।

6. जलमार्गों में प्रदूषण

भारत की उभरती आबादी और तेजी से शहरी क्षेत्रों का विस्तार करने से इसकी नदियों पर भारी टोल आया है, जो बुरी तरह प्रदूषित और विकास से दबाए गए हैं। जल प्रदूषण भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत इलाज नहीं किया गया है सीवेज। प्रदूषण के अन्य स्रोतों में कृषि रनऑफ और अनियमित लघु उद्योग शामिल हैं। भारत में ज्यादातर नदियों, झीलों और सतही जल प्रदूषित हैं।

अनुचित डिजाइन या खराब रखरखाव या पौधों को संचालित करने के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की कमी के कारण सरकार के स्वामित्व वाले सीवेज उपचार संयंत्रों में से अधिकतर समय अनुपस्थित कर्मचारियों और खराब प्रबंधन के साथ बंद रहता है। इन क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट जल आमतौर पर मिट्टी या वाष्पीकरण में घुल जाता है। अनियंत्रित अपशिष्ट शहरी क्षेत्रों में जमा होता है जो निर्जलीकरण की स्थिति पैदा करता है और प्रदूषण को मुक्त करता है जो सतह और भूजल में छिड़कता है।

हैदराबाद के प्रौद्योगिकी केंद्र में, कार्यकर्ता 2015 में एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, ताकि शहर की मुसी नदी के पास अवैध निर्माण को रोका जा सके। चेन्नई में, दक्षिण भारत में, नागरिकों ने कोउम नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल से याचिका दायर की है, साथ ही साथ गंध को हटाने और प्रवाह में सुधार के लिए एक बड़े नहर की उचित खुराक सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की है। नई दिल्ली में, कार्यकर्ताओं ने मेट्रो डिपो और सड़क समेत असंख्य विकास से मुक्त, यंगुना की एक प्रमुख सहायक यमुना के बाढ़ के मैदान और नदी के बिस्तर को बनाए रखने के लिए सालों से एक और कानूनी मामला लड़ रहा है। और पवित्र भारतीय गंगा, जो पांच भारतीय राज्यों के माध्यम से चलती है, बुरी तरह दूषित नदी को साफ करने की सरकार की योजना की विफलता से निराश पर्यावरणविदों और नागरिकों द्वारा कानूनी लड़ाई के केंद्र में रही है।

नदियों और धाराओं ने भारत में हालिया शहरी विस्फोट की झुकाव पैदा की है, एक ऐसा देश जिसकी आबादी पिछले 40 वर्षों में लगभग दोगुना हो गई है, 1.35 बिलियन हो गई है। अनियोजित विकास ने जल निकायों के उपयोग को सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग किया है।
इस दुर्व्यवहार की लागत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। पिछले साल एक अध्ययन ने यमुना नदी में गंभीर प्रदूषण के लिए नई दिल्ली में टाइफोइड, हेपेटाइटिस और दस्त के बढ़ते मामलों को जोड़ा, जो शहर के अधिकांश पेयजल प्रदान करता है। यमुना के बड़े हिस्सों के साथ-साथ चेन्नई के कोउम और मुंबई की मिठी और उल्हास नदियों को मृत क्षेत्रों माना जाता है, जिसमें ज्यादातर मछली जीवन का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन के स्तर बहुत कम होते हैं।

7. मॉनसून बारिश - जल निकासी के मुद्दे और झीलों और बांधों में पानी भंडार करने की कमी

मानसून भारत के कृषि-निर्भर $ 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए जीवनशैली है, क्योंकि कम से कम आधे खेतों में बारिश होती है। जून-सितंबर मानसून के मौसम में देश को सालाना बारिश का लगभग 70% मिलता है, जिससे अनुमानित 263 मिलियन किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

लगभग 800 मिलियन लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर करते हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 15% है और एक असफल मानसून देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर एक प्रभावशाली प्रभाव डाल सकता है।

मानसून का देश के कृषि जीडीपी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। मुख्य खरीफ, या गर्मी की रोपण, चावल, चीनी गन्ना, दालें और तिलहन जैसी फसलें जून में मानसून बारिश के आगमन से शुरू होती हैं।

ग्रीष्मकालीन फसलों का भारत के खाद्य उत्पादन में लगभग आधा हिस्सा होता है और देरी या खराब मॉनसून का अर्थ खाद्य मुद्रास्फीति में आपूर्ति के मुद्दों और त्वरण का मतलब है, एक प्रमुख मीट्रिक जो भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दरों पर निर्णय को प्रभावित करती है।

घाटे के मानसून से सूखा जैसी स्थिति भी हो सकती है, जिससे ग्रामीण घरेलू आय, खपत और आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। एक खराब मॉनसून न केवल तेजी से चलने वाले उपभोक्ता सामान, दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और ग्रामीण आवास क्षेत्रों की कमजोर मांग को जन्म देता है बल्कि आवश्यक खाद्य स्टेपल के आयात को भी बढ़ाता है और सरकार को कृषि ऋण छूट जैसे उपाय करने के लिए मजबूर करता है, जिससे दबाव डाला जाता है वित्त। जबकि एक सामान्य मानसून के परिणामस्वरूप अच्छी फसल होती है, जो बदले में ग्रामीण आय में वृद्धि करती है और उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च बढ़ाती है। इसका जल विद्युत परियोजनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मानसून बारिश की अनियमितताओं पर भरोसा करने के लिए, भारत कहते हैं, विशेषज्ञों को अपने अभी भी कम जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। समुद्र और नदियों में चलने से मानसून बारिश के दौरान बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है, छोटे झीलों और बांधों का निर्माण जवाब हो सकता है? प्रारंभिक सूखा चेतावनी प्रणाली विकसित करने और तेज भविष्यवाणियों को प्रदान करने के लिए मौसम संबंधी उपकरणों में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

भारत को अपने विशाल खाद्य भंडारों को भी प्रबंधित करने की जरूरत है - इस वर्ष की शुरुआत में 60 मिलियन टन से ज्यादा - बेहतर। बहुत अधिक भोजन नष्ट हो जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि एक मानसून मानसून पूर्वानुमान की तुलना में एक बड़ी त्रासदी है।

8. विश्वविद्यालयों और पंचायत भ्रष्टाचार सहित रिश्वत और भ्रष्टाचार

एक मुद्दा है जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों की भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न केवल अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से पीछे रखा है, लेकिन भ्रष्टाचार ने देश के विकास को रोक दिया है। पारदर्शिता इंटरनेशनल ने बताया कि लगभग 50% भारतीयों के पास सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा की जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने या संपर्कों का उपयोग करने का पहला हाथ अनुभव था।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कार्यक्रम और सामाजिक खर्च योजनाएं हैं। भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत के ट्रकिंग उद्योग में शामिल हैं, जिन्हें सालाना रिश्वत में अरबों रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है और पुलिस अंतरराज्यीय राजमार्गों पर रुक जाती है। मीडिया ने व्यापक रूप से भ्रष्ट भारतीय नागरिकों के स्विस बैंकों में लाखों रुपये छेड़छाड़ के आरोप प्रकाशित किए हैं। स्विस अधिकारियों ने इन आरोपों से इंकार कर दिया, जिन्हें बाद में 2015-2016 में साबित किया गया।

भारतीय मीडिया को काफी हद तक भ्रष्ट राजनेताओं और उद्योगपतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो जनता को गलत जानकारी के साथ गुमराह करके और राजनीतिक और व्यापार विरोधियों पर मिट्टी के झुकाव के लिए मीडिया का उपयोग करके एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

भूमि और संपत्ति - अधिकारियों को राज्य संपत्ति चोरी करने का आरोप है। पूरे भारत में शहरों और गांवों में, नगरपालिका और अन्य सरकारी अधिकारियों के समूह, निर्वाचित राजनेता, न्यायिक अधिकारी, रियल एस्टेट डेवलपर्स और कानून प्रवर्तन अधिकारी, अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण, विकास और बिक्री करते हैं।

सरकारी अनुबंध - सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण समस्याएं पूरे देश में होती हैं। विश्व बैंक के अनुसार, सहायता कार्यक्रम भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और अंडर-पेमेंट से घिरे हैं। एक उदाहरण के रूप में, रिपोर्ट बताती है कि गरीबों के लिए केवल 40% अनाज सौंपा गया लक्ष्य अपने लक्षित लक्ष्य तक पहुंचता है।

सरकारी अस्पतालों में, भ्रष्टाचार दवाओं की अनुपलब्धता / नकल, प्रवेश प्राप्त करने, डॉक्टरों के साथ परामर्श और नैदानिक सेवाएं प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है।

विश्वविद्यालयों और स्कूलों - रिश्वत और भ्रष्टाचार व्यापक शिक्षा संस्थान हैं, जिससे धनवान माता-पिता स्कूलों के प्रवेश के लिए रिश्वत का भुगतान करते हैं, एक बार फिर, दुख की बात है कि गरीब लोगों को छोड़ दिया जाता है।

9. कचरे और स्वच्छता

'कचरे के उपमहाद्वीप' - इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप को अक्सर स्थानीय प्रेस में संदर्भित किया जाता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है: भारतीय शहरों में खासतौर से खराब इलाकों में, हरियाली, सड़कों और चौकों में अपशिष्ट देखा जा सकता है, प्लास्टिक के बक्से और प्लास्टिक के थैले, चमकदार रंगीन पैकेजिंग और खाद्य अपशिष्ट, पुराने समाचार पत्र और गत्ते के बक्से हैं।

लेकिन अपशिष्ट सिर्फ शहरों में जमा नहीं होता है। स्थानीय सड़कों पर एक दिन भविष्य के पुरातात्विकों को आसानी से नीचे पहुंचने की इजाजत दी जाएगी कि 'दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र' के निवासियों की खाने की आदतें कैसे विकसित हुई हैं।

कुकीज़ की विभिन्न किस्मों, सर्वव्यापी प्लास्टिक की बोतलों, जंगली प्लास्टिक बैगों के सभी प्रकार के पैकेज जिनमें एक बार मिठाई, च्यूइंग गम और चिप्स का कॉर्नुकोपिया होता है - इन सभी चीजों को अक्सर 'सजावट' सड़क के किनारे के डिब्बे और रेलवे पर फेंक दिया जाता है तटबंधों।

हालांकि, तथाकथित अच्छे जिलों में अपशिष्ट का निपटारा अभी भी किया जाता है। यह पारंपरिक जाति के व्यवसायों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं, रैग-पिकर्स और क्लीनर के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनके लिए अपशिष्ट के पहाड़ आय का स्रोत हैं, और यह स्थानीय मानकों द्वारा काफी महत्वपूर्ण है।

कचरा हल किया जाता है और बाहर रखा जाता है: अपशिष्ट कागज, लौह और गैर-लौह धातु, कांच, और रैग और पुराने कपड़े जो धोए जाते हैं और मिश्रित होते हैं। कुछ भी जिसे पुन: उपयोग किया जा सकता है पुनर्विक्रय किया जाता है। लेकिन कचरे के कलेक्टरों द्वारा भी जो भी पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है, अक्सर गरीब पड़ोसियों की सड़कों पर फिर से बाहर फेंक दिया जाता है, जहां यह गर्म दक्षिणी सूरज में वर्षों से घिरा हुआ है, जो एक सजातीय ग्रे-ब्राउन मश में घुल रहा है।

कचरे का हमला

देश की राजधानी नई दिल्ली विशेष रूप से 'आक्रामक अपशिष्ट' से प्रभावित है। स्वच्छता श्रमिकों की उपनिवेशों में से एक राजनयिक तिमाही के मध्य में स्थित है, जिसमें घुमावदार बेकार पैक और दूर से दिखाई देने वाले रैग से भरे बैग के पिरामिड हैं, जो राजनयिक मिशन और दूतावास विला के मेहमानों को आश्चर्यचकित करते हैं। रैग-पिकर्स की जाति बहुत समय पहले बस गई थी - इससे पहले कि विशाल राजनयिक तिमाही इसे सभी तरफ घिरा हुआ था। शहर के अधिकारियों ने ऐसे 'गैर राजनयिक' पड़ोसियों को पुनर्स्थापित करने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन 'अपशिष्ट तिमाही' के निवासियों ने जिद्दी विरोध किया है और छोड़ना नहीं चाहते हैं।

आंकड़े चौंकाने लगे हैं: आधिकारिक और अनधिकृत शहर डंप हर दिन 10,000 टन कचरे को जोड़ते हैं। पत्रकारों का अनुमान है कि इसका मतलब प्रतिदिन 2,300 ट्रक है। हालांकि, आबादी के साथ अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है, और यह उम्मीद है कि 2025 तक, दैनिक अपशिष्ट मात्रा 4,700 ट्रकलोड तक पहुंच जाएगी।

एक भारतीय पत्रकार ने एक बार इस आलेख के लेखक से कहा कि परंपरागत रूप से, भारत में कचरा सड़क पर फेंक दिया गया था (जैसा कि यह एक बार कई यूरोपीय शहरों में था), और गर्म भारतीय सूरज इसे धूल में सूख जाएगा। लेकिन, आधुनिक प्लास्टिक, पैकेजिंग और कार्डबोर्ड के आगमन के साथ, यह 'कचरा निपटान प्रणाली' अब काम नहीं करता है। फिर भी परंपरा बनी हुई है। आज तक, कई भारतीय शहरों में, कचरे को फेंकने के लिए इसे समझने योग्य नहीं माना जाता है, जहां आप खड़े हो जाते हैं या फिर बिना किसी शर्मिंदगी के अपने आप को राहत देते हैं। अपशिष्ट अक्सर नदियों में फेंक दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, लेकिन नदी के किनारे पहुंचने का भी एक अप्रिय अनुभव है - 'पवित्र जल' पुराने गटर की तरह गंध करता है। जीवाणु को छोड़कर कुछ भी नहीं, इस नदी में लंबे समय तक रहता है।

समस्या सिर्फ एक विशेष परिवार या उसके शिक्षा स्तर की समृद्धि नहीं है। अमीर पड़ोसियों के कई निवासी भी कचरा कलेक्टरों के लिए कचरा डिब्बे या बैग को उनके सामने वाले दरवाजे से कचरा लेने के लिए इंतजार नहीं करना चाहते हैं। अमीर नागरिक बैकस्टेट में कचरा फेंकने के लिए एक नौकर भेज देंगे।

हालांकि, समस्या स्पष्ट रूप से न केवल भारतीयों की आदतों के साथ है, बल्कि परंपरागत जाति व्यवस्था के आधार पर देश के अपशिष्ट की सफाई की पुरानी व्यवस्था के साथ है। अधिकांश भारतीय शहरों में हर घर से अपशिष्ट संग्रह और निपटान का आधुनिक केंद्रीकृत तंत्र नहीं होता है। दिल्ली में, उदाहरण के लिए, कचरा केवल 25% क्षेत्र से ही एकत्र किया जाता है। अधिकृत लैंडफिल पर पैकेज खींचना एक लंबी यात्रा है। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पड़ोसी जिलों के निवासियों द्वारा किसी भी खाली या छोड़े गए आंगन को लैंडफिल में बदल दिया गया है।

फिर भी, एकत्रित किए जा रहे अपशिष्ट के साथ भी एक समस्या मौजूद है। राजधानी के पास चार प्रमुख लैंडफिलों में से तीन पहले ही क्षमता से अधिक हो चुके हैं और उन्हें बंद करने की जरूरत है। लेकिन भारत में नई लैंडफिल के लिए कोई जगह नहीं है, जो पहले से ही अधिक प्रचलित है।

नई दिल्ली के लिए समस्या अद्वितीय नहीं है। उदाहरण के लिए, मुंबई में, कचरे के पहाड़ इतने बड़े हैं कि भरे उपनगरों को अब संजय गांधी रिजर्व के तेंदुए से तेंदुए द्वारा अक्सर देखा जाता है - शिकारी बिल्लियों को भोजन की तलाश में घूमते हैं और आस-पास रहने वाले लोगों के लिए

खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा, 'भारत की आर्थिक राजधानी' में हवा काफी प्रदूषित है, कम से कम कचरे के जलन की वजह से नहीं।

देश के दक्षिण में बैंगलोर शहर (कभी-कभी भारतीय सिलिकॉन घाटी कहा जाता है), 'नई प्रौद्योगिकियों की राजधानी', इसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के साथ-साथ रोजाना 3,000-4,000 टन कचरा भी पैदा करता है। इस उभरते शहर में अपशिष्ट भंडारण के लिए अंतरिक्ष की समस्या इतनी तीव्र है कि सरकार ने एक समय में कलाकार निकोलस रोरीच के बेटे स्वेतोस्लाव रोरीच, और उनकी पत्नी और भारतीय फिल्म स्टार द्वारा स्थापित ताटागुनी संपत्ति के बाहरी इलाके में स्थित क्षेत्र की मांग करने के लिए भी सोचा था। देविका रानी स्वेतोस्लाव रोरीच का उद्देश्य संपत्ति पर एक संग्रहालय स्थापित करना था, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं ने 450 एकड़ के मनोरंजक पार्क का उपयोग लैंडफिल के रूप में करने का फैसला किया। रूसी दूतावास और भारतीय जनता के प्रयासों के लिए धन्यवाद, संग्रहालय इस प्रयास से लड़ने में कामयाब रहा।

विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी उम्र और समृद्धि के आधार पर 'दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र' का हर नागरिक, हर दिन 200 से 600 ग्राम कचरे का उत्पादन करता है। इस अपशिष्ट सामग्री को बहने वाली लैंडफिल, अंधा गलियों, शहरी बैकस्टेट, और सड़कों और रेलवे लाइनों के साथ छुट्टी में एकत्रित किया जाता है, जिससे नगर पालिकाओं से शिकायतें होती हैं और शहर के आसपास और आसपास बिखरे हुए सभी कचरे को साफ करने की असंभवता होती है।

जबकि अधिकारी शिकायत करते हैं कि पर्यावरणविद एक एसओएस संकेत भेज रहे हैं, अपर्याप्त अपशिष्ट भारतीय शहरों में पहले से ही मुश्किल सेनेटरी और महामारी विज्ञान की स्थिति में सुधार करने में मदद नहीं करेगा। और यदि यह चल रहा है, तो कचरा लोगों को विस्थापित करना शुरू कर देगा।

झाड़ियों के साथ सितारे

"यह कोई असाधारण नहीं है। विभिन्न स्रोतों के मुताबिक, भारत के शहर प्रतिदिन 100,000 टन ठोस कचरे का उत्पादन करते हैं। सरकार प्रति टन कचरे से 500 से 1,500 रुपए खर्च करती है: इस राशि का 60-70 प्रतिशत कचरा संग्रह पर खर्च किया जाता है, परिवहन पर 30 प्रतिशत अधिक, और बाकी शेष पांच प्रतिशत रीसाइक्लिंग पर खर्च किया जाता है, "व्लादिमीर Ivashin ने कहा , ब्रिक्स बिजनेस मैगज़ीन के साथ एक साक्षात्कार में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियन फॉर इंडोलॉजिकल स्टडीज में विशेषज्ञ।

Ivashin ने कहा, अधिकांश अपशिष्ट जला दिया या दफनाया गया है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस आबादी वाले देश में लैंडफिल साइटों के लिए जगह खोजने की आवश्यकता इतनी तीव्र है। इसके अलावा, कचरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान को भारतीयों के कचरे और साफ सड़कों की ओर रुख में एक कट्टरपंथी बदलाव की आवश्यकता होगी।

10. प्लास्टिक प्रदूषण

हमारे कारों और बसों और हमारे फोन और कार्यालयों में, हमारे पालतू जानवरों, हमारे डाइनिंग टेबल और रसोई पर, हर जगह प्लास्टिक का एक छोटा सा प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बिना दुनिया की कल्पना करना लगभग असंभव है

हम प्लास्टिक बैग और बच्चों की पहुंच से बाहर प्लास्टिक पैकेजिंग को रखते हुए लगभग हमेशा प्लास्टिक बैग और पैकेज पर घुटनों की चेतावनी लेते हैं। लेकिन हम ग्रह के साथ सावधान नहीं रहे हैं। उत्पादित 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक में से 6.3 अरब टन छोड़ दिया गया है। हर साल, लगभग 13 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे महासागरों में जोड़े जाते हैं। उनकी स्थायित्व को देखते हुए, प्लास्टिक विघटित नहीं होते हैं।

पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने बताया, "प्लास्टिक की बोतल 450-1000 साल के बीच विघटन के लिए होती है।"

प्लास्टिक उत्पादन में अधिकांश वृद्धि एकल उपयोग या डिस्पोजेबल अनुप्रयोगों द्वारा संचालित होती है। उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक का लगभग 50% एकल उपयोग उत्पादों जैसे बोतलों, प्लास्टिक के थैले, पैकेजिंग, स्ट्रॉ, हलचल, चम्मच और कांटे हैं। दुनिया भर में, हर मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक पीने की बोतलें खरीदी जाती हैं। हर साल हम 5 ट्रिलियन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं।

भारत में, कुल प्लास्टिक खपत का 80% कचरे के रूप में त्याग दिया जाता है और आधिकारिक आंकड़ों का कहना है कि देश रोजाना 25, 940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। इस अपशिष्ट का कम से कम 40% अनचाहे है।

कंपनियों द्वारा कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के रीसाइक्लिंग को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास भी है। लेकिन बैग, कैंडी रैपर, तंबाकू और पैन मसाला sachets, साबुन wrappers और शैम्पू sachets जैसे अन्य एकल उपयोग प्लास्टिक या तो बहुत मुश्किल या इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं। इन प्लास्टिक की वस्तुओं को फिर लैंडफिल, अनधिकृत कचरा डंप में अपना रास्ता मिलते हैं, या बस सड़क के किनारों पर अचयनित रहते हैं।

आखिरकार, इन एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं नदियों, अन्य जल निकायों और महासागर clog। वे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, और अक्सर हमारे खाद्य प्रणालियों में अपना रास्ता खोजते हैं।

इस साल फरवरी में, पटना में बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज में लाए गए एक बूढ़े और संक्रमित छः वर्षीय गाय पर चल रहे पशु चिकित्सकों ने अपने पेट से 80 किलोग्राम प्लास्टिक हटा दिया। यद्यपि यह पहली बार नहीं था कि डॉक्टरों ने पशु के पेट से पॉलिथिन हटा दिया था, यह एक से एक किलोग्राम 80 किलोग्राम था। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि डॉक्टरों ने पशु के पेट से पॉलिथिन हटा दिया था, लेकिन एक जानवर से 80 किलोग्राम एक रिकॉर्ड था।

11. बहुत से सार्वजनिक छुट्टियों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कम उत्पादकता

भारत, सांस्कृतिक रूप से विविध और उत्साही समाज होने के नाते, विभिन्न छुट्टियों और त्यौहार मनाता है। जब सार्वजनिक छुट्टियों की बात आती है, तो भारत में दो विश्व रिकॉर्ड होते हैं, जो यह व्यवसाय परिप्रेक्ष्य के बिना कर सकता है। सबसे पहले, यह दुनिया में सबसे अधिक (प्रति वर्ष 20 से अधिक) है, और दूसरी बात, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश की अपनी स्थानीय अवकाश है। भारत में केवल तीन राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश हैं, और बाकी सभी क्षेत्रीय हैं।

अत्यधिक सार्वजनिक छुट्टियां अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को चोट पहुंचाती हैं। जब ये छुट्टियां 'उचित सीमा' से अधिक हो जाती हैं, तो देश की उत्पादकता पर प्रतिकूल समझौता होने की संभावना है। यह अक्सर यह भी नहीं समझा जाता है कि अंतःस्थापित और अनियोजित छुट्टियां देश के वित्तीय और पूंजी बाजारों को वैश्विक रुझानों के साथ बनाने के लिए तैयार किए गए प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। छुट्टियों का भारत में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी पर स्थानीय प्रभाव या दूरस्थ रूप से स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ये चुनौतियां आउटसोर्स आईटी या व्यावसायिक प्रक्रियाओं वाली कंपनियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जो अपने भारतीय समकक्षों के साथ दूरस्थ रूप से काम करते हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार मीटिंगों के लिए आमने-सामने मिलते हैं।

एसएलए (सेवा स्तर समझौते) साल भर की सेवा की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के लिए नहीं, जिसका मतलब है कि जब आप सोचते हैं कि आपके प्रमुख संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। छुट्टियों और सामान्य सप्ताहांत के उचित सेट के साथ, आधुनिक बैंकिंग के साथ कुछ हद तक धीरे-धीरे गति रखने के लिए सहनशील हो सकता है। लेकिन असंगत और बड़ी संख्या में सार्वजनिक छुट्टियों और गैर-कामकाजी छुट्टियों वाले देश में, देश की वित्तीय वृद्धि को रोक दिया जा सकता है।

भारतीय छुट्टियों को काम के प्रवाह में बाधा के रूप में देखा जाता है। वे क्या हैं, वे कैसे मनाए जाते हैं, और सांस्कृतिक रूप से वे क्या संकेत करते हैं में बहुत रुचि नहीं है। भारतीय छुट्टियों के कैलेंडर के सटीक ज्ञान और भारत के साथ काम करने के लिए इन कैलेंडर के आसपास योजना बनाने के लिए भी दुर्लभ है। यहां बिंदु यह है कि आपको क्षेत्रीय रूप से सोचना होगा। यदि आप भारत के चार अलग-अलग शहरों से निपटते हैं, तो प्रत्येक एक अलग राज्य में, छुट्टियों में थोड़ी सी अंतर दिखाई देगी। चूंकि निजी कंपनियों के पास कौन सी छुट्टियां देखने के लिए चुनने में काफी अक्षांश है, आपको यह भी जानने की जरूरत है कि विभिन्न कंपनियों की छुट्टियों की सूची क्या है।

नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए, छुट्टियां खुदरा, मनोरंजन और यात्रा और पर्यटन जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए भी वरदान हैं, जो भारत में ऐसे अवसरों पर बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में लोगों को खरीदारी करने के लिए अधिक समय देने से खर्च बढ़ सकता है और बदले में विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दुशेरा, आईडी, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्यौहार हर साल बिक्री राजस्व में अरबों रुपए का उत्पादन करते हैं।

भारत एक बेहद विविध देश है, और विविधता कार्यस्थल से बाज़ार तक कई अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि, यह चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। धर्म और कार्यस्थल तेजी से अंतर्निहित हो रहे हैं। अधिक श्रमिकों को धार्मिक विश्वासों का अभ्यास करने के लिए कार्यदिवस के दौरान छुट्टियों और समय का जश्न मनाने के लिए दिन के साथ कार्यस्थल में उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समायोजित करने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर, ये आवास लंबे समय से आम हैं। अधिकांश देशों में एक प्रमुख धर्म के साथ आबादी है, जिसमें कार्यस्थल, सार्वजनिक अवकाश और सामाजिक मूल्यों सहित देश के जीवन के कई पहलुओं में परिलक्षित प्रथाएं होती हैं।

आम तौर पर, यह स्पष्ट है कि छुट्टियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शायद सूक्ष्म आर्थिक स्तर के रूप में व्यापक आर्थिक स्तर के रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं। व्यावसायिक दिनों के नुकसान को कम करने से सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, व्यापार के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों की अतिरिक्त आय की आय कमाने में मदद मिल सकती है, जो छुट्टियों पर मिस पाती है।

12. शिक्षा में संकट

सीबीएसई के नतीजे खत्म हो गए हैं और छात्र विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए ढेर में दाखिला ले रहे हैं। जबकि बच्चों को अपने जीवन-यात्रा के अगले अध्याय पर लगना रोमांचक लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण मांग-आपूर्ति के मेल के कारण चिंताजनक और तनावपूर्ण अभ्यास भी है और आगे, कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से कोई भी शीर्ष 100 क्यूएस में शामिल नहीं है रैंकिंग। असाधारण योग्यता वाले छात्रों के लिए, यह एक बड़ी निराशा हो सकती है। भारत के आकार और आकांक्षा के देश के लिए, यह एक बड़ी विफलता है।

भारत के शिक्षा संकट के पीछे कारण इस क्षेत्र की दिशा में सात दशक के दृष्टिकोण में हैं। अनुसंधान हमारी संस्कृति में कभी भी एम्बेडेड नहीं था और शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षण के साथ समान थी। नतीजतन, हमारा दृष्टिकोण स्थैतिक और बुकिश होने लगा और केवल स्कूल में कितने गए थे इस पर ध्यान केंद्रित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर, यह एक बुरी बात नहीं है। हम अन्यथा बच्चों को शिक्षा का अधिकार अस्वीकार करेंगे और कई को बाल मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। 200 9 में आरटीई कानून के अधिनियमन के साथ, लगभग 260 मिलियन बच्चे आज भारत में स्कूल जाते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल प्रणाली बनाते हैं। सरकार द्वारा संचालित एक मिलियन से अधिक 1.5 मिलियन स्कूल हैं। शिक्षा बाजार वर्तमान में 100 अरब डॉलर मूल्यवान है और 2020 तक दोगुना हो गया है। यह प्रभावशाली है।

लेकिन भारत को जो चाहिए वह शिक्षा का अधिकार नहीं बल्कि गुणवत्ता शिक्षा का अधिकार है। एक प्रतिष्ठित भारतीय पत्रिका में कुछ साल पहले एक परेशान रिपोर्ट के मुताबिक, हमारे इंजीनियरिंग स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत नियोक्ता हैं।

जब तक कि शिक्षा प्रणाली काफी हद तक पुनर्जीवित न हो और वास्तव में, हम अपने युवा आबादी की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएंगे और इस प्रकार हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को खो देंगे। इसके अंदर से हमारी शिक्षा प्रणाली के बहुत डीएनए को बदलने की आवश्यकता है। सरकार इसे पहचानती है और पिछले कई महीनों में, नई शिक्षा नीति के रूप में पहलों की एक श्रृंखला पर चर्चा चल रही है।

दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश, भारत कैसे प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से निरंतर बजटीय आवंटन के बिना एक महत्वाकांक्षी एजेंडा होना चाहिए और प्रणाली को क्या समझता है इसकी स्पष्ट समझ है।

निष्पक्ष होने के लिए, समस्या की तीव्र परिमाण भयभीत है। पिछले दशकों में, हम शुतुरमुर्ग-जैसे आत्म-भ्रम के साथ बह गए हैं। हम ज्ञान अर्थव्यवस्था की बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए जोखिम-प्रतिकूल और अंधे हुए हैं। हमारे अधिकांश स्कूलों में न केवल बुनियादी सुविधाएं बल्कि शिक्षकों की कमी है। जहां शिक्षक उपलब्ध हैं, बहुमत अधिक विस्तारित और कम योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे स्नातक नियोक्ता नहीं हैं।

एक राष्ट्र का भविष्य अपनी शिक्षा प्रणाली द्वारा जाली है। एक निष्क्रिय प्रणाली एक निराशाजनक भविष्य में आ जाएगा। हमें बाजार के हिस्से के संबंध में काफी हद तक एक समान खतरे का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे शैक्षिक संस्थानों में से अधिकांश सरकारी स्वामित्व वाले और संचालित होते हैं। लेकिन अशुभता एक वास्तविक और विश्वसनीय खतरा है।

हमें जो सवाल पूछना है वह शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दूसरे शब्दों में, हम शिक्षा से प्राप्त करने की क्या उम्मीद करते हैं। यह वास्तव में दो चीजों में से एक है: या तो छात्र या शिक्षक शिक्षा प्रणाली के लिए केंद्र है।

प्राचीन काल से, शिक्षा, या शिक्षा के लिए हमारा दृष्टिकोण शिक्षक, गुरु, शिश्या या शिष्य के बीच संबंध रहा है। शिक्षा जानकारी प्रदान नहीं कर रही थी, बल्कि गहरे ज्ञान के बारे में जो अध्ययन और अनुभव के वर्षों से आती है।

दुर्भाग्यवश, हम मानते हैं कि यह वही है जो हमारी शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है! नतीजतन, ज्यादातर शिक्षकों गुरु का आवरण करते हैं। वे वास्तव में, अनुशासनार्थी हैं, जो पुलिसकर्मियों जैसे कक्षाओं को चलाते हैं।

दुनिया भर में, प्रौद्योगिकी ने कल के शिक्षक को बदल दिया है। हम अब पिछली शताब्दी की पद्धति का उपयोग करके आधुनिक दिन शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की गले लगाने और सोच में विघटनकारी बदलाव हमारी शिक्षा नीति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है।

बस रखें, शिक्षक केवल पेंसिल को तेज करता है और प्रत्येक छात्र को अंतर्निहित प्रतिभा के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं जानते कि कैसे सिखाया जाए। बल्कि वे वास्तव में नहीं जानते कि वे क्यों सिखाते हैं। शिक्षकों को यह पहचानने की आवश्यकता है कि छात्र सिस्टम के लिए केंद्र हैं और वे, शिक्षक के रूप में, केवल सहायक हैं और कुछ भी नहीं।

इसके लिए एक मौलिक अनुवांशिक बदलाव की आवश्यकता है जो हमारी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह तभी हो सकता है जब हम सोच की स्वायत्तता को गले लगाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम जिज्ञासा और इस प्रकार रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे। इसे प्राप्त करने के लिए, हमारे शिक्षकों को शिक्षित होने की आवश्यकता है।

विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियों में वैचारिक फोकस नहीं है लेकिन पूरी तरह से बाजार संचालित हैं। बाजार की तरह, वे भविष्य की उम्मीद करते हैं और यह पता लगाते हैं कि इसे नेविगेट करने की सर्वोत्तम आवश्यकता है। यदि भारत का भविष्य शिक्षा की गुणवत्ता द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो दिमाग को नाटकीय रूप से बदलना होगा। जैसा कि एचजी वेल्स ने हमें याद दिलाया: "सभ्यता शिक्षा और आपदा के बीच एक दौड़ है।" हमारी पसंद यह निर्धारित करेगी कि हम कहां जा रहे हैं। समस्या यह है कि हम समय से बाहर चल रहे हैं।

13. ग्रामीण विकास

भारत उच्च विकास दर और हमारे शहरों और शहरी केंद्रों को समृद्धि के अंक प्रदर्शित करने के लिए शुरू करने वाली अर्थव्यवस्था के साथ एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। फिर भी, कोई समान विकास नहीं है, ग्रामीण हिनटरलैंड शहरी भारत के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहा है। हमारे 70 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं, हमारे गरीबों का 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में भी रहते हैं। आर्थिक विकास के लाभ लोगों के दो तिहाई से अधिक नहीं हो रहे हैं। विकास के दृश्य प्रतीकों से हमें ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन विकास पैटर्न एक समान नहीं है। जबकि विनिर्माण, सेवाओं और संचार क्षेत्रों के विकास की दर में काफी सुधार हुआ है, कृषि, आधारभूत संरचना विकास, और समुदाय और सामाजिक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और ग्रामीण विकास में, हमारे प्रदर्शन की सराहना नहीं है।

ग्रामीण लोगों के विकास के बिना, देश कभी भी विकसित होने का दावा नहीं कर सकता है। हाल के वर्षों में, कृषि विकास गिर गया है और इसलिए कृषि की निवेश और लाभप्रदता, फसलों के तहत शुद्ध बोया क्षेत्र और सिंचाई के तहत क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2006-2007 के मुताबिक, लगभग सभी फसलों में प्रति इकाई क्षेत्र में कम उपज नियमित रूप से बन गई है।

ग्रामीण भारत संकट में है। डॉ। एमएस स्वामीनाथन, प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री, ने कहा, "कृषि संकट की जड़ें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पतन में हैं ... बेरोजगारी की वजह से परिसंपत्ति-कम से बाहर प्रवास बढ़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र है अधिकांश वस्तुओं के लिए परिचालन नहीं करना। आजीविका सुरक्षा व्यवस्था के हर स्तर पर गरीबी से लाभ उठाने की प्रवृत्ति है। ग्रामीण इलाकों में कुछ गड़बड़ है ... "

आज, विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के मुकाबले खुद को असहाय लगाना , देश के कुछ हिस्सों में किसान चरम उपायों का सहारा ले रहा है। अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तनों के कारण बार-बार फसल विफलताओं, खेती की बढ़ती लागत को पूरा करने में असमर्थता, और बढ़ते कर्ज का बोझ निराशा की वजह से कारकों में से एक है। ऐसे परिदृश्य में, ग्रामीण पुनर्निर्माण की चुनौतियों का सामना करना एक भयानक और प्राथमिक कार्य बन जाता है।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यह जरूरी है कि हमारे पास स्थगन से क्षेत्र को खत्म करने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध कार्यक्रम है, अगर मंदी नहीं है। बड़ी सिंचाई सुविधाओं, बेहतर बीज और कृषि इनपुट, और उचित लागत पर उर्वरक को वित्त और बुनियादी ढांचे और विपणन सुविधाओं के साथ किसानों को प्रदान किया जाना होगा। कृषि आय उत्पन्न

करने वाली गतिविधि बननी चाहिए और किसानों को मौसम, वित्तीय संसाधनों और बाजारों के विचलन के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में उत्पादकता और रोजगार उत्पादन में वृद्धि के लिए, मुख्य रूप से भूमि सुधारों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि समर्थन मूल्य और सस्ते क्रेडिट के प्रावधान किसी बिंदु से परे मदद नहीं करते हैं। अनुभव से पता चला है कि गरीबों को जमीन तक पहुंच प्रदान करना विकास विरोधी नहीं है। ग्रामीण विकास रणनीति में, छोटे परिवार के खेतों की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ग्रामीण विकास में समस्याएं

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 60-70% ग्रामीण आबादी प्राचीन स्थितियों में रहती है। स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी यह खेदजनक स्थिति मौजूद है। ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति में भी तात्कालिकता हो। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कई बाधाएं हैं जो नीचे हैं

1. कई गांवों में बिजली की आपूर्ति नहीं है।

2. खाना पकाने, रहने और खेती के प्राचीन तरीकों का उपयोग करने वाले कई ग्रामीण लोग और इन तरीकों पर उनका भरोसा है।

3. आदिम खाना पकाने के स्टोव का उपयोग करके, लगभग 300,000 मौत / वर्ष प्रदूषण के कारण योजना लेता है।

4. भारत की 54% आबादी 25 साल से कम है और उनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम रोजगार के अवसरों के साथ रहते हैं।

5. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में साक्षरता प्रमुख समस्या है।

8. हर कोई शहरों में जाना चाहता है, इसलिए ग्रामीण लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

9. निजीकरण अवधारणा ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी है, लेकिन सरकार इस पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है।

10. नीति निर्माता ग्रामीण लोगों के सुधार के लिए नीतियां, कार्यक्रम तैयार करते हैं, लेकिन यदि इन कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जाता है तो उनका कोई उपयोग नहीं होता है।